GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 21st August , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय**	डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया
Page 06 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	भारत, जापान ने इंडो-पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए '2+2' वार्ता की
Page 10 **Syllabus : GS 3 : पर्यावरण**	इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम पर
Page 12 **Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था**	'मुद्रास्फीति लक्ष्य को छोड़ना प्रतिकूल हो सकता है'
समाचार में शब्द	मियावाकी विधि
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था**	स्थायी सामूहिक रोजगार के लिए एक आधारभूत योजना
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	विषय: अफ्रीकी संघ

Page : 01 : GS 2 : Social Justice : Issues related to women

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया।

- एनटीएफ अस्पताल परिसर में सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेगा; अलग-अलग शौचालयों सहित बुनियादी ढांचे का विकास; महत्वपूर्ण अस्पताल क्षेत्रों तक पहुंच को सीमित करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप; सीसीटीवी कैमरे; रात्रि परिवहन का प्रावधान; परामर्श सेवाएं; संकट कार्यशालाएं; त्रैमासिक सुरक्षा ऑडिट; और अस्पतालों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाएगी।

SC forms task force to ensure doctors' safety

Taking up a *suo motu* case over the rape and murder of a doctor, court asks task force to recommend security measures, safety audits, and enhanced police presence; it gives Centre a month to collate data from States and Union Territories on security and facilities at all government-run hospitals; top court asks CBI to submit its report tomorrow

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday constituted a National Task Force to work out the modalities of safety measures for medical professionals. The NTF will recommend security measures on hospital premises; infrastructure development, including separate restrooms; technological interventions to limit access to critical hospital areas; CCTV cameras; provision of night transport; counselling services; crisis workshops; quarterly safety audits; and enhanced police presence in hospitals.

A three-judge Bench, headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, explaining why the court had taken *suo motu* cognisance of the rape and murder of a junior doctor at the State-run R.G. Kar Medical College and Hospital in Kolkata, said the case laid bare the systemic failure in providing safety to medical professionals.

The court said the "horrific" crime was the last straw and "the nation cannot wait for another rape and murder in order to bring in safety laws for medical professionals and doctors".

The Centre was given a month to collate data from States and Union Territories on security and infrastructure facilities at all government-run hospitals. This would include whether they have complied with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Doctors of RML Hospital watch a live-stream of the Supreme Court hearing in New Delhi on Tuesday. SHASHI SHEKHAR KASHYAP

Surgeon Vice-Admiral Arti Sarin, Director General Medical Services (Navy); D. Nageshwar Reddy, Chairperson and Managing Director, Asian Institute of Gastroenterology and AIG Hospitals, Hyderabad; M. Srinivas, Director, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi; Pratima Murthy, Director, National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bengaluru; Goverdhen Dutt Puri, Executive Director, AIIMS, Jodhpur; Saumitra Rawat, Chairperson, Institute of Surgical Gastroenterology and Member, Board of Management, Sir Ganga Ram Hospital, Delhi; Anita Saxena, Vice-Chancellor, Pandit B.D. Sharma Medical University, Rohtak; Pallavi Saple, Dean, Grant Medical College, Mumbai and Sir J.J. Group of Hospitals, Mumbai; and Padma Srivastav, former Professor, Neurology Department, AIIMS, Delhi, currently serving as Chairperson of Neurology, Paras Health, have been appointed members of the NTF. The Cabinet Secretary; the Union Home and Family Welfare Secretaries; the Chairperson, National Medical Commission; and President, National Board of Examinations will function as its ex-officio members.

"There is a virtual absence of safety for doctors, especially young women doctors. They have 36-hour shifts. We need a national protocol for safe conditions of work for doctors and medical personnel... It is not that every time there is a rape and murder, the conscience of the nation is awakened. We need a protocol not just on paper, but to be actually implemented," Chief Justice Chandrachud said.

The Chief Justice said women medical professionals were especially vulnerable to sexual assaults. Gender violence in the medical profession was a matter of very serious concern.

The Chief Justice reached out to the protesting doctors and medical staff to resume work, saying their concerns would be given the highest priority by the Supreme Court. The top court warned the West Bengal government against "unleashing" its might on protestors.

The Bench directed the CBI, which is currently in charge of the investigation into the crime on the orders of the Calcutta High Court, to submit its report on August 22.

REGRESSIVE MOVE
» PAGE 8

Ex-principal booked on graft allegations

KOLKATA

The Kolkata Police has booked Sandip Ghosh, the former principal, on allegations of corruption and irregularities and sent him a notice to appear before the police allegedly for disclosing the identity of the victim. » PAGE 4

समाचार के बारे में:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बताया कि अदालत ने कोलकाता में सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का स्वतः संज्ञान क्यों लिया, उन्होंने कहा कि इस मामले ने चिकित्सा पेशेवरों को सुरक्षा प्रदान करने में प्रणालीगत विफलता को उजागर किया है।
- "डॉक्टरों, विशेष रूप से युवा महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षा का अभाव है। उनकी 36 घंटे की शिफ्ट होती है। हमें डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के लिए काम की सुरक्षित परिस्थितियों के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की आवश्यकता है... ऐसा नहीं है कि हर बार बलात्कार और हत्या होने पर राष्ट्र की अंतरात्मा जाग जाती है। हमें एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है जो केवल कागज पर न हो, बल्कि वास्तव में लागू हो," मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा।

स्वतः संज्ञान के बारे में

- स्वतः संज्ञान: कानून में, "स्वतः संज्ञान" शब्द का अर्थ है किसी भी पक्ष द्वारा कोई औपचारिक शिकायत या याचिका प्रस्तुत किए बिना अपनी पहल पर मामलों की सुनवाई करने का न्यायालय का अधिकार। मीडिया रिपोर्ट, पत्रों या किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर, न्यायालय स्वयं ही प्रक्रियाएँ शुरू करता है।

- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मामलों का स्वतः संज्ञान लेने की क्षमता है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर समान अधिकार दिया गया है।
- जनहित याचिकाएँ: जनहित याचिका (पीआईएल), एक प्रक्रिया जो लोगों या सामाजिक कार्यकर्ताओं को जनहित की ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाती है, अक्सर स्वतः संज्ञान से जुड़ी होती है। इस विचार ने सामाजिक न्याय और सार्वजनिक सरोकार के मुद्दों में न्यायपालिका की भागीदारी के दायरे को बढ़ा दिया है।
- न्यायिक सक्रियता: स्वतः संज्ञान को न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण माना जाता है, जिसमें न्यायाधीश उन दबावपूर्ण चिंताओं को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है जिन्हें अन्यथा अनदेखा या उपेक्षित किया जा सकता है। ऐसे मामलों को अपने हाथ में लेकर न्यायालय न्याय के त्वरित और प्रभावी प्रशासन की गारंटी देने की उम्मीद करते हैं।
- न्यायिक समीक्षा का दायरा: आम तौर पर ऐसे व्यक्ति से याचिका की आवश्यकता होती है जिसके साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन न्यायालयों ने कभी-कभी अनुचित आदेशों या अन्यायों को संबोधित करने के लिए स्वतः संज्ञान लिया है।

ऐसे मामले जहां स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाता है

- भारतीय न्यायालयों द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लिए गए कुछ मामले इस प्रकार हैं:
  - o न्यायालय की अवमानना: न्यायालय की अवमानना को कानून, मानदंडों और आचार संहिता की अनदेखी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका न्यायालय में पालन किया जाता है। न्यायालय अक्सर ऐसे अधिकारी के खिलाफ स्वप्रेरणा से अवमानना का मामला लाता है जो न्याय प्रशासन में बाधा डालता है या न्यायालय के सम्मान को कमजोर बनाता है।
  - o नए मामले के लिए जांच का आदेश देना: न्यायालय को किसी भी सरकारी एजेंसी, पुलिस विभाग, सीबीआई या अन्य एजेंसी द्वारा किसी भी स्तर पर जांच का आदेश देने का अधिकार है, अगर उसे लगता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। न्यायालय किसी भी वृत्तचित्र, समाचार या मीडिया स्रोत से जानकारी के आधार पर या प्रभावित व्यक्तियों के समूह के पत्र के जवाब में भी कार्रवाई कर सकता है।
  - o पुराने/बंद मामलों को फिर से खोलना: यदि मामला बंद होने के बाद कोई नया और पर्याप्त सबूत मिलता है, तो न्यायालय मामले को फिर से खोलने के लिए स्वप्रेरणा से कार्रवाई कर सकता है।

Page 06 : GS 2 : International Relations : Bilateral Groupings & Agreements

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत-जापान साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के व्यापक संदर्भ में स्थापित है और यह आगे भी बढ़ती रहेगी। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच "2+2" वार्ता का नया संस्करण आयोजित किया।

2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बारे में

- 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता 2018 से हर साल आयोजित होने वाला एक राजनयिक शिखर सम्मेलन है, जो शुरू में भारत और अमेरिका के बीच होता था।
- बाद में इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूनाइटेड किंगडम को शामिल किया गया।
- इस वार्ता में भाग लेने वाले देशों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आम चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- इस वार्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच 2017 के समझौते के दौरान रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता की जगह ली।
- पहली शिखर वार्ता 6 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें रक्षा साझेदारी और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई थी।

भारत-जापान 2+2 वार्ता की प्रमुख प्राथमिकताएँ क्या हैं?

- सुरक्षा सहयोग को अपडेट करें: वर्तमान रणनीतिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए 2008 के सुरक्षा समझौते को संशोधित करना।
- एक मुक्त हिंद-प्रशांत को बढ़ावा देना: एक मुक्त, खुला और स्थिर

India, Japan conduct '2+2' dialogue with focus on Indo-Pacific

Two sides hold discussion on defence cooperation, significance of open Indo-Pacific; Rajnath says partnership is based on democratic values

Press Trust of India
NEW DELHI

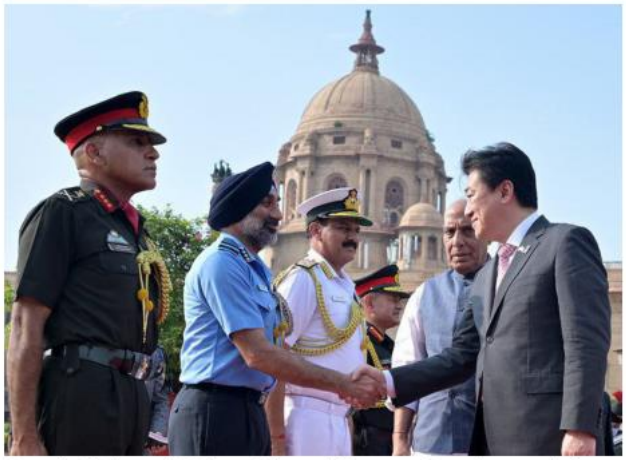

Japan's Minister of Defence Minoru Kihara receives the guard of honour in the presence of Rajnath Singh. SHASHI SHEKHAR KASHYAP

The India-Japan partnership is set against a larger context of a free, open and rules-based Indo-Pacific and it will continue to grow, External Affairs Minister S. Jaishankar said on Tuesday as both sides held a fresh edition of "2+2" dialogue amid China's increasing military muscle-flexing in the region.

The Japanese delegation at the talks in Delhi was headed by Foreign Minister Yoko Kamikawa and Defence Minister Minoru Kihara. Mr. Jaishankar and Defence Minister Rajnath Singh headed the Indian team.

"In the last decade, our relationship has assumed the form of a special strategic and global partnership. The logic of this evolution is our expanding interests and growing activities," Mr. Jaishankar said.

"As we both step forward into a more volatile and unpredictable world, there is a need for reliable partners with whom there are substantial convergences," he said.

"As a result, we have consciously sought to facilitate each other's endeavours, comprehend each other's objectives, strengthen each other's positions and work with other nations of shared comfort," he added.

In his remarks, Mr. Singh said the India-Japan special strategic and global partnership is based on democratic values and the rule of law.

He said India has set a goal of becoming a developed country by 2047 and building domestic defence capabilities is one of the significant aspects of this vision.

"The India-Japan partnership in the defence sector will be an important aspect to realise our goal. Let us make a vision for this partnership," the Defence Minister said.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना।

- रणनीतिक वार्ता में शामिल होना: द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच रणनीतिक चर्चा करना।
- क्षेत्रीय सुरक्षा को संबोधित करना: चीनी मुखरता, रूस-यूक्रेन युद्ध और गाजा संकट जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना।
- क्वाड प्रयासों का समन्वय करना: संभावित शिखर सम्मेलन सहित क्वाड ढांचे के भीतर सहयोग की खोज करना।

UPSC Mains PYQ : 2020

प्रश्न: चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) वर्तमान समय में एक सैन्य गठबंधन से एक व्यापार ब्लॉक में परिवर्तित हो रहा है, चर्चा करें।

GEO IAS
It's about quality

Page 10 : GS 3 : Enviroment : Clean Energy

भारत 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जो उत्पादन और क्षमता में वृद्धि द्वारा चिह्नित है।

On the ethanol blending programme

India is on its way to achieve its target of blending 20% of petrol with ethanol by 2025-26. However, the food versus fuel equation continues to hang over the ethanol economy along with questions regarding fuel efficiency in existing vehicles

ECONOMIC NOTES

M. Kalyanaraman

India is on its way to achieve its target of blending 20% of petrol with ethanol by 2025-26, going by the milestones on blending percentages crossed so far and the increase in ethanol production capacity.

However, the food versus fuel equation continues to hang over the ethanol economy as recent events have shown. For example, maize import has increased from April to June of this year compared to last year at a time when maize has been used to produce more fuel ethanol to compensate for restrictions on using sugarcane products. The industry, however, opines India has enough grain and sugar surpluses. Tarun Sawhney, Vice-Chairman and Managing Director, Triveni Engineering and Industries, says, "With big food stocks across the country, there is absolutely no concern about food security in the near future. I am concerned the supplies and stocks are so large that it could lead to wastage and spoiling," he said.

All the emphasis has been on first generation (1G) ethanol that is directly made from foodgrains and sugarcane. The government should diversify and move to 2G and 3G that are more benign in terms of impact on food security.

Status of ethanol production capacity

Twenty per cent by 2025-26 would mean producing some 1,000 crore litres of ethanol for blending with petrol. "We are now seeing 13% to 15% blending with a sharp increase since 2021," says Sourabh Banerjee, consultant on ethanol and biofuels. In 2021, the blending was around 8%. Deepak Ballani, director general of Indian Sugar and Bio-energy Manufacturers Association, says the sugar industry has invested some ₹40,000 crore in the last few years in capacity expansion. In just two years, 92 crore litre capacity was added.

The roadmap for achieving ethanol blending targets, prepared by the Niti Aayog, had laid down that the capacity of sugarcane-based distilleries would need to increase from 426 crore litres in 2021 to 760 crore litres in 2026, while grain-based distilleries' capacity should increase from 258 to 740 crore litres. In other words, a lot more of grain-based distilleries were to come up. Besides fuel ethanol, some 310 crore litres would be needed for making ethanol for consumable liquor as well as industrial uses. Taking stock in December 2023, the government said India's ethanol production capacity had already increased to 1,380 crore litres – some 875 crore litres capacity from sugarcane and 505 crore from foodgrains. This means the targeted total ethanol capacity is nearly achieved although with a greater sugarcane-based component.

Two interest subvention programmes for establishing new distilleries had facilitated the ramping up of ethanol generation capacity. Industry has been demanding, that to maintain momentum and create surplus capacity for other uses such as blending with diesel, these programmes should be extended and that Oil Marketing Companies (OMCs) should sign more long-term contracts with distilleries until the supply chain is well and truly formed.

Sugarcane gives rise to three main related products – sugarcane juice and syrup, B-heavy molasses and C-heavy molasses, in the order of decreasing sugar content. The first two would typically go to making sugar while the third will be used for ethanol production. In a bid to up fuel ethanol production, the government had started permitting the diversion of the first two away from sugar production to fuel ethanol. Ethanol pricing depends on the sugar content of the input. In 2022-23, 63% of fuel ethanol came from B-heavy molasses and 33% from molasses. In December, 2023, the government restricted the diversion of the first two over fears of falling sugar stocks.

Mr. Ballani, however, believes the restrictions will be removed this year. He says that out of a total production of 340 lakh tonnes of sugar in 2023-24, consumption was only 285 lakh tonnes. Some closing stock is therefore available for 2023-24, he says, adding that fears of depleting sugar surpluses are unfounded.

Expanding sugarcane production will have to be sustained by higher water use. Souvik Bhattacharjya of The Earth Research Institute says to sustain 50% of 1,000 crore litres from sugarcane, 400 billion litres of water would be needed additionally. Expanding sugarcane cultivation would redirect irrigation water from essential food-grain crops, exacerbating concerns about agricultural sustainability, he says. To make up for the shortfall due to restrictions on B-heavy molasses, grain-based distilleries, mainly maize, have likely been operating at full capacity to keep up with the blending percentages this year.

Government policy is that maize as well as surplus rice and damaged grains will be used to feed grain-based distilleries.

India ranks as a major maize producer globally, but domestic consumption consistently outpaces production, says TERI's Bhattacharjya. Over the last few years, Indian maize imports have been hovering around 0.4 to 0.5 million tonnes a year. A rapid diversion to ethanol will drive up prices and negatively impact its major uses – the poultry sector by 47%, followed by livestock feed (13%) and starch (14%). At 3 to 4 tonnes per hectare, India's maize yield is much lower than other countries, he adds.

Commerce Ministry data show that in 2023-24, Indian maize (corn) imports were $39 million. This year, from April to June, the import is already worth $103 million. As per NITI Aayog's estimates, some 4.8 million hectares will have to be added to maize cultivation area to meet the 20% target, which is almost half of the typical maize cultivation area.

On fuel efficiency in automobiles

Ethanol will not only reduce greenhouse gas emissions, it will also prevent an estimated foreign exchange outgo of some $4 billion per year, as per Maruti Suzuki company estimates, and bolster the rural economy by promoting the cultivation of various crops through an assured market. Many vehicle makers say the government deadline of E20 (20% ethanol and 80% gasoline) compliance is achievable, but questions remain over existing vehicles whose performance would be affected by higher ethanol content.

The NITI Aayog report notes that ethanol brought down fuel efficiency in vehicles not suited for ethanol by an average of 6%.

Many vehicle makers say they are in line with the government deadline of 2025. A Maruti Suzuki spokesperson told *The Hindu* that all Maruti vehicles have been compatible with E-20 fuel since April 2023. Existing vehicles may have to go for an engine retuning and change over to E20 supported material depending on what grade they are.

How different States view the policy

Meanwhile, the developing ethanol economy has impacted States differently. While the fuel ethanol pricing is the same across India, States determine the pricing of Extra Neutral Alcohol (ENA) that goes into making liquor for consumption and other uses. That pricing has been a decider for sugarcane-based distilleries in opting for highly pure fuel ethanol vis-a-vis ENA and other forms.

In Uttar Pradesh, the government reserves some 25% of the ethanol for ENA. Mr. Sawhney says that ENA is less attractive since it offers lower value. Ethanol made from molasses, especially B-heavy molasses, offers significantly higher value, he adds. U.P. is fully aligned with the central government's mission on ethanol, says Mr. Sawhney. U.P. is the single largest contributor to the ethanol blending program nationwide, he adds. "Most of the distilleries especially in U.P., as well as new capacity coming up, are multi-fuel, allowing them to process both sugarcane juice and molasses, and grain, including rice and maize. For the upcoming year, it is anticipated that 55% of the national requirement of ethanol will be met from sugarcane and the balance 45% would be met by grain distilleries."

In Tamil Nadu, where liquor is a highly lucrative market for distilleries, fuel ethanol has not yet caught on as much. The State government procures and sells all the liquor. Liquor revenue is one-sixth of all government revenue.

An increase in sugarcane cultivation may not be possible because of water requirements, industry sources say. Broken rice may not be made available either. A highly placed government source said it would be bad politics in Tamil Nadu to supply rice, even broken rice, to ethanol since people will relate it to liquor and oppose. M. Ponnuswamy, Chairman and Managing director of Pon Pure Chemicals, advocates that the government should support maize cultivation as an alternative. "Maize is not water intensive. It degrades soil and cannot be the sole crop either. It can be used in rotation with sugarcane to ensure that soil fertility is not degraded," he says. Some half a dozen distilleries for fuel ethanol are on the drawing boards and at various stages of completion. Assuring feedstock supply can help to promote a non-sugarcane distillery base in the State.

Vishal Kamat, Chairman Confederation of Indian Industry (CII) Maharashtra, says in Maharashtra it is more profitable to make ENA and supply it for other uses such as manufacturing activities, fashion and medicine than for ethanol blending. "All segments besides liquor are experiencing good demand thanks to a booming economy. This said, if there is a steady contract for procurement in blending then fuel ethanol can be attractive since additional processing will not be required after purity is ensured," he said.

Many across the industry demand an increase in ethanol pricing.

Ethanol for blending

With the government restricting the use of B-heavy molasses and sugarcane juice for ethanol production from December 2023, grain-based ethanol production has increased to maintain blending percentages

Ethanol supplied to oil marketing companies

Supply-year	C-heavy molasses	B-heavy molasses	Sugarcane juice	Surplus rice	Damaged grains	Maize	Total in litre crore; blending % in brackets
2019-20	74	68	15	0	16	0	173 (5.00)
2020-21	39	183	39	2	39	0	302 (8.10)
2021-22	11	265	85	49	24	0	434 (10.02)
2022-23	6	235	128	74	32	32	506 (12.06)
2023-24*	39	95	56	0	76	135	401 (13.00)

Supply years are December-November, December to October for 2022-23 and November to October for 2023-24 *Data available only for November-June

Shortage: Sugar mill workers load harvested sugarcane on to a tractor trolly in Sangli district, in Maharashtra, in 2022. REUTERS

THE GIST

- The roadmap for achieving ethanol blending targets, prepared by the Niti Aayog, had laid down that the capacity of sugarcane-based distilleries would need to increase from 426 crore litres in 2021 to 760 crore litres in 2026, while grain-based distilleries' capacity should increase from 258 to 740 crore litres.
- Ethanol will not only reduce greenhouse gas emissions, it will also prevent an estimated foreign exchange outgo of some $4 billion per year, as per Maruti Suzuki company estimates, and bolster the rural economy by promoting the cultivation of various crops through an assured market.
- Meanwhile, the developing ethanol economy has impacted States differently. While the fuel ethanol pricing is the same across India, States determine the pricing of Extra Neutral Alcohol (ENA) that goes into making liquor for consumption and other uses.

- हालांकि, मक्का के बढ़ते आयात और गन्ने के लिए पानी के उपयोग के कारण खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।
- इन चुनौतियों के साथ इथेनॉल उत्पादन को संतुलित करना नीतिगत चर्चाओं में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों का अवलोकन

- भारत का लक्ष्य 2025-26 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण करना है, जिसमें मिश्रण प्रतिशत में मील के पत्थर और इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रगति दर्ज की गई है।
- इस लक्ष्य में लगभग 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन शामिल है। वर्तमान मिश्रण दर 13% से 15% के बीच है, जो 2021 में लगभग 8% से उल्लेखनीय वृद्धि है।
- इथेनॉल उत्पादन क्षमता में काफी विस्तार हुआ है, जो दिसंबर 2023 तक 1,380 करोड़ लीटर तक पहुँच गया है, जिसमें गन्ने से 875 करोड़ लीटर और खाद्यान्न से 505 करोड़ लीटर है।

खाद्य बनाम ईंधन बहस

- खाद्य बनाम ईंधन समीकरण चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि के कारण मक्का के आयात में वृद्धि हुई है, जो कि इथेनॉल उत्पादन में इसके उपयोग के कारण है, जो कि गन्ना उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंधों के कारण और भी बढ़ गया है।
- उद्योग का तर्क है कि भारत में पर्याप्त खाद्यान्न और चीनी अधिशेष है, लेकिन बड़े खाद्य भंडार के कारण संभावित बर्बादी और खराब होने की चिंताएँ हैं।
- खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, पहली पीढ़ी (1G) इथेनॉल से दूसरी पीढ़ी (2G) और तीसरी पीढ़ी (3G) इथेनॉल में विविधता लाने का आह्वान किया जा रहा है, जो खाद्य संसाधनों पर कम प्रभाव डालते हैं।

इथेनॉल उत्पादन क्षमता और निवेश

- 20% मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इथेनॉल उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं।
- चीनी उद्योग ने अकेले क्षमता विस्तार में लगभग ₹40,000 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें दो वर्षों में 92 करोड़ लीटर नई क्षमता जोड़ी गई है।
- वर्तमान इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग लक्ष्य तक पहुँच गई है, लेकिन इसमें गन्ना आधारित इथेनॉल का अनुपात अधिक है।

सरकारी नीतियाँ और उत्पादन की गतिशीलता

- ब्याज अनुदान कार्यक्रमों ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता के विस्तार का समर्थन किया है।
- इन कार्यक्रमों को विस्तारित करने और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हासिल करने की उद्योग जगत की मांग है, ताकि गति बनाए रखी जा सके और अधिशेष क्षमता बनाई जा सके।
- गन्ने के उत्पादों को इथेनॉल उत्पादन में बदलने से बी-भारी गुड़ और गन्ने के रस के उपयोग पर प्रतिबंध लग गए हैं, जिससे चीनी के भंडार प्रभावित हो सकते हैं।
- चीनी अधिशेष कम होने की आशंकाओं को निराधार माना जाता है, इसलिए ये प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं।

पानी का उपयोग और स्थिरता संबंधी चिंताएँ

- इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गन्ने के उत्पादन का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है।
- गन्ने से 1,000 करोड़ लीटर में से 50% को बनाए रखने के लिए, अतिरिक्त 400 बिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होगी, जो आवश्यक खाद्य फसलों से सिंचाई को हटाकर कृषि स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
- गुड़ पर प्रतिबंधों की भरपाई के लिए, मुख्य रूप से मक्का का उपयोग करने वाली अनाज आधारित भट्टियाँ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।

आर्थिक और कृषि प्रभाव

- भारत, एक प्रमुख मक्का उत्पादक, इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का के उपयोग के कारण मक्का के आयात में वृद्धि और संभावित मूल्य वृद्धि का सामना कर रहा है।

- यह पोल्ट्री क्षेत्र और मक्का के अन्य प्रमुख उपयोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- वाणिज्य मंत्रालय ने 2023-24 में मक्का के आयात में $39 मिलियन से इस वर्ष अप्रैल-जून की अवधि में $103 मिलियन तक की उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी।
- 20% मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए, पर्याप्त अतिरिक्त मक्का की खेती की आवश्यकता है, जो सामान्य खेती क्षेत्र को प्रभावित करती है।

वाहन प्रदर्शन और राज्य-स्तरीय प्रभाव

- इथेनॉल मिश्रण से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आने और विदेशी मुद्रा की बचत होने की उम्मीद है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
- हालांकि, उच्च इथेनॉल सामग्री मौजूदा वाहनों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, जिसके लिए इंजन को फिर से ट्यून करने या E20-समर्थित सामग्रियों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।
- विभिन्न राज्य इथेनॉल नीति को अलग-अलग तरीके से देखते हैं। कुछ राज्यों में, ईंधन इथेनॉल मूल्य निर्धारण और शराब उत्पादन पर इसका प्रभाव इथेनॉल उत्पादन के आकर्षण को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्य गन्ने से इथेनॉल उत्पादन को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य मक्का जैसे विकल्पों पर विचार करते हैं।

निष्कर्ष

- भारत में इथेनॉल उत्पादन के विस्तार में खाद्य सुरक्षा, जल उपयोग, आर्थिक प्रभाव और राज्य-स्तरीय नीतियों का जटिल अंतर्संबंध शामिल है।
- जबकि मिश्रण लक्ष्यों की दिशा में प्रगति उल्लेखनीय है, खाद्य सुरक्षा और स्थिरता संबंधी चिंताओं के साथ इथेनॉल उत्पादन को संतुलित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC Prelims PYQ : 2020

प्रश्न: भारत की जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है?

(1) कसावा
(2) क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने
(3) मूंगफली के बीज
(4) कुलथी
(5) सड़े हुए आलू
(6) चुकंदर

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 2, 5 और 6
(b) केवल 1, 3, 4 और 6
(c) केवल 2, 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (a)

Page 12 : GS 3 : Indian Economy

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था ने अच्छा काम किया है और इसे छोड़कर अधिक विवेकाधीन व्यवस्था अपनाना जोखिम भरा और प्रतिकूल हो सकता है, दो अर्थशास्त्रियों ने एक नए शोध पत्र में तर्क दिया है।

- 'भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: एक और आकलन' शीर्षक वाले पत्र के लेखकों ने कहा कि भारतीय परिवारों की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए CPI मुद्रास्फीति टोकरी में खाद्य-मूल्य मुद्रास्फीति का भार कम किया जाना चाहिए।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है?

- न्यूजीलैंड में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को पहली बार अपनाए जाने के तीन दशक हो चुके हैं और उसके बाद 33 अन्य देशों ने भी इसे अपनाया।
- भारत ने इसे 2016 में अपनाया।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति को 2 से 6 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा के भीतर लगभग 4 प्रतिशत पर सीमित रखना था।
- RBI ने अब नीतिगत साधन की औपचारिक समीक्षा की घोषणा की है।
- अक्टूबर 2016 में RBI मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक में, यह भी औपचारिक रूप से घोषित किया गया था कि MPC ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तटस्थ वास्तविक नीति दर के रूप में 1.25 प्रतिशत की वास्तविक रेपो दर पर विचार किया है।
- तटस्थ वास्तविक नीति दर से आरबीआई का तात्पर्य संभावित वृद्धि (यानी पूर्ण रोजगार पर वृद्धि) के अनुरूप नीति दर से है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत आरबीआई के 3 रुख

1. 'समायोज्य': एक उदार रुख का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन की आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है। एक उदार नीति अवधि के दौरान केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करने के लिए तैयार है। दर वृद्धि से इनकार किया जाता है।
2. 'तटस्थ': एक 'तटस्थ रुख' से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक या तो दर में कटौती कर सकता है या दर बढ़ा सकता है। यह रुख आम तौर पर तब अपनाया जाता है जब नीति प्राथमिकता मुद्रास्फीति और विकास दोनों पर समान होती है।
3. 'हॉकिश': एक हॉकिश रुख इंगित करता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम रखना है। ऐसे चरण के दौरान, केंद्रीय बैंक धन की आपूर्ति को रोकने और इस प्रकार मांग को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करने के लिए तैयार है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की प्रभावशीलता

सफलताएँ

- औसत मुद्रास्फीति में गिरावट आई है: जीडीपी डिफ्लेटर के माध्यम से मापी गई औसत मुद्रास्फीति दर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था में काफी कम हो गई है।
  - o मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से पहले पाँच वर्षों में औसत मुद्रास्फीति 5.69 प्रतिशत थी, जो पिछले पाँच वर्षों में घटकर 3.47 प्रतिशत रह गई है।
- सीपीआई में गिरावट: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2011-2015 की अवधि के दौरान 8.26 प्रतिशत से घटकर 2016-2019 में 4.99 प्रतिशत हो गई, जो 3.27 प्रतिशत अंकों की गिरावट है।
  - o यह मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण वाले देशों के साथ-साथ इसे न अपनाने वाले देशों में भी सबसे अधिक है।
- बढ़ी हुई पारदर्शिता: मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचे को अपनाने के बाद भारत में मौद्रिक नीति पारदर्शिता में सुधार हुआ है।

विफलताएँ

- मुद्रास्फीति पर एकमात्र ध्यान: हालाँकि, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के कुछ आलोचकों का मानना है कि मूल्य स्थिरता पर इसका एकमात्र ध्यान विकास की अनिवार्यताओं को अनदेखा करता है।
- भारत में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं: भारत में, कृषि क्षेत्र और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, जो इस तरह की दरों में बढ़ोतरी से सीधे प्रभावित नहीं होता है, जिससे बढ़ोतरी कम प्रभावी हो जाती है।

क्या राजकोषीय घाटे ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में भूमिका निभाई?

- 2003 में, भारत ने राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए FRBM अधिनियम पारित किया।
- घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राजकोषीय घाटे के मुद्रास्फीति को प्रभावित करने के बारे में बहुत कम सबूत हैं।
- FRBM घोषणा से पहले लगातार तीन वर्षों के लिए, समेकित केंद्र और राज्य घाटे ने 10.9 प्रतिशत (2001 में), 10.4 और 10.9 प्रतिशत दर्ज किया।
- सात साल की 1999-2005 की अवधि के लिए, समेकित राजकोषीय घाटे का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 9.4 प्रतिशत था।
- फिर भी, ये वर्ष FRBM और आईटी के बिना भारतीय मुद्रास्फीति के स्वर्णिम काल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की लागत

- भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की लागत भी है।
- इससे वास्तविक नीतिगत दरें बढ़ गईं, यह गलत धारणा थी कि उच्च नीतिगत दरें खाद्य, तेल या किसी अन्य चीज़ की कीमत को प्रभावित करती हैं।
- लेकिन उच्च वास्तविक दरें इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में घरेलू पूंजी की लागत को प्रभावित करके आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।
- यह बहुत संभव है कि यह संयोग न हो कि संभावित जीडीपी वृद्धि, जैसा कि आरबीआई ने स्वीकार किया है, सितंबर 2016 में एमपीसी द्वारा निर्णय लेने से ठीक पहले पहुंच गई थी।
- तब से वास्तविक नीतिगत दरों में लगातार वृद्धि हुई है, और जीडीपी वृद्धि में लगातार गिरावट आई है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: इस प्रश्न पर विचार करें कि "भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण तंत्र किस हद तक सफल रहा है? अपने तर्क के समर्थन में कारण बताएँ।"

Term In News : Miyawaki Method

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में मियावाकी पद्धति से पौधे लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया।

मियावाकी विधि के बारे में:

- यह जापानी वनस्पतिशास्त्री और पादप पारिस्थितिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित वनरोपण की एक विधि है।
- इसमें हर वर्ग मीटर में दो से चार प्रकार के देशी पेड़ लगाए जाते हैं।
- घने रोपण के कारण, पौधे सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए तेज़ी से बढ़ते हैं।
- केवल उन देशी प्रजातियों को लगाया जाता है जो उस क्षेत्र में मनुष्यों के बिना स्वाभाविक रूप से पाए जा सकते हैं, विशिष्ट जलवायु स्थिति को देखते हुए।
- किसी दिए गए क्षेत्र में रोपण के लिए प्रजातियों का चयन मूल रूप से संभावित प्राकृतिक वनस्पति (PNV) के सिद्धांत से जुड़ा था, दूसरे शब्दों में, वह वनस्पति जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पाए जा सकते हैं।
- इस विधि में, पेड़ आत्मनिर्भर हो जाते हैं और तीन साल के भीतर अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं।
- मियावाकी वन 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, 30 गुना घने होते हैं और उनमें 100 गुना अधिक जैव विविधता होती है।
- वे जल्दी से स्थापित हो जाते हैं, पहले दो-तीन वर्षों के बाद रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है, और उन्हें 3 वर्ग मीटर जितनी छोटी जगहों पर भी बनाया जा सकता है।
- मियावाकी तकनीक के लक्ष्यों में जैव विविधता में सुधार, कार्बन को अलग करना, हरित आवरण को बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना और जल स्तर को संरक्षित करना शामिल है।
- मियावाकी वन उन शहरों के लिए व्यवहार्य समाधान हैं जो जलवायु लचीलापन तेजी से विकसित करना चाहते हैं।
- यह प्रभावी है क्योंकि यह प्राकृतिक पुनर्वनीकरण सिद्धांतों पर आधारित है, यानी, क्षेत्र के मूल पेड़ों का उपयोग करना और प्राकृतिक वन पुनर्जनन प्रक्रियाओं की नकल करना।

UPSC Prelims PYQ : 2014

प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

कार्यक्रम/परियोजना : मंत्रालय

1. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम: कृषि मंत्रालय
2. रेगिस्तान विकास कार्यक्रम: पर्यावरण और वन मंत्रालय
3. राष्ट्रीय जलग्रहण विकास: ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए परियोजना

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 3
c) 1, 2 और 3
d) कोई नहीं

उत्तर: (d)

GEO IAS
It's about quality

A ground plan for sustainable mass employment

Amarjeet Sinha
a retired civil servant

These 12-point policy initiatives can pave the way for employment with dignity

The big Budget announcement of five major employment-related schemes sounds impressive. The schemes are to have an ambitious ₹2 lakh crore outlay spread over five years to facilitate jobs and skilling and other opportunities for 4.1 crore youth. The Economic Survey has made a strong case for employment, goading the private sector to create jobs, the reasons being lower taxes since 2019 and higher profits post the COVID-19 pandemic. The Prime Minister's package for employment must be seen along with other initiatives for human well-being.

Any evidence-based road map for sustainable mass employment with dignity must begin by recognising the race to the bottom on wages, when unlimited unskilled workers are available. Let us not forget that the Periodic Labour Force Survey 2019-20 had found that a wage earner is in the top 10% if he/she earns ₹25,000 a month. Short-duration skill programmes have had low long-term placements. This is often on account of wage being low for a life of dignity in urban areas. Many went back to their villages to do something else.

Evidence also points to the continuum of education and skills. Monthly per capita consumption is the highest in States such as Tamil Nadu, Kerala, Himachal Pradesh, Goa and Sikkim. These States have better human development indicators as well. Odisha, in spite of pushing short duration skilling, has a low per capita consumption in the absence of robust higher secondary/higher/vocational opportunities in institutions.

Mass employment with dignity requires productivity increases. While it is fine for the Economic Survey to urge the private sector to create jobs, it must be understood that the state also has a role in determining the floor rate of wages and in assuring high quality public goods. There is enough evidence that public employment per unit of population in India is much lower than what it is in most of the developed world. What should the key policy initiatives in creating sustainable mass employment with dignity be?

Skilling needs

First, begin from below through decentralised community action, to identify skilling needs. Ownership by a community of State programmes only comes through direct community action. The *gram sabha* or *basti samitis* in urban areas can play a critical role in taking government programmes to the people. The steps can be as follows: Create a register of all those wanting employment/self-employment. Create a plan for every youth in partnership with professionals at the cluster level. Well-educated professionals are needed on fixed-term appointment at the local government level, to ensure evidence-based outcomes. Make it the basis for finding skill providers and employers. Let apprenticeships too base themselves on such a community connect. The result will be transformational. Let us begin from below.

Second, converge initiatives for education, health, skills, nutrition, livelihoods, and employment (at the local government level) with women's collectives. This will ensure community accountability, with untied funds, functions and functionaries for effective quality outcomes. Employment does not improve in isolation. All human development indicators achieve better when they devolve and converge. Untied funds are transformational as communities make effective choices. India's failures in public goods (education, health, nutrition, environment, and sanitation) can improve through such an approach. We need to put in more money in these sectors, through decentralised community action.

Education and employability

Third, introduce need-based vocational courses/certificate programmes alongside undergraduate programmes (B.A., B.Sc., B. Com.) in every college. This has been done in the past. It needs to be made compulsory in every college. Give them the resources to experiment. For example, there are some colleges in Mumbai that provide certificate courses (with graduation) such as tourist guide, counsellor, and so on. This will greatly improve employability on scale. Make graduation programmes employable.

Fourth, standardise nursing and allied health-care professional courses in all States according to international benchmarks. Nurses, geriatric care-givers, and health paramedics are required on scale in and outside India. The biggest problem is the uneven quality of institutions and the absence of a standardised course curriculum and duration. We need to standardise these skill sets to international standards.

Fifth, create community cadres of care-givers to run crèches universally so that women can work without fear. We have a four- to six-hour anganwadi service but the number of infants is more than what a crèche care-giver can manage. We need to create a community cadre of crèche care-givers, who can be paid by the local governments/women's collective after intensive training. The Community Resource Persons of the Rural Livelihood Mission is a good model to follow. Community cadres can have multiple livelihoods in agriculture, animal rearing, non-farm opportunities, and retail shops.

Sixth, invest in Industrial Training Institutes (ITI), polytechnics as hubs in skill development for feeder schools. The absence of quality and up-to-date infrastructure in many ITIs, polytechnics, and Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) is a very critical gap in an age of upskilling and re-skilling. Institutions have to be autonomous and community managed. These technical institutions can also work as a hub for feeder schools. Schools must develop an equivalence framework for academic and vocational inputs in terms of credits and hours. The focus should be on States/districts with the least institutional structure for vocational education. Tamil Nadu and Maharashtra have large capacity that has helped manufacturing in those States. Human capital matters.

Seventh, introduce enterprise and start-up skills through professionals in high schools. Schools need to introduce technology and enterprise as a subject at the upper primary/high school-level onwards. It is important that experimentation and innovation with an understanding of business processes are a part of the regular school curriculum. Visits by professionals to schools can impart finishing skills to students; employment/enterprise follows.

Eighth, have a co-sharing model of apprenticeships with industry on scale. This is critical as far as manufacturing sector opportunities or even the services sector is concerned. Skilling costs must be shared with potential employers as standalone government-funded skilling is not always the best way forward. Unless industry has a stake in the apprenticeship, it does not work.

Capital loans and enterprises

Ninth, streamline working capital loans for women-led enterprises/first-generation enterprises to enable them to go to scale. The lessons from the lakhpati didis of the Rural Livelihoods Mission bring out the challenges in getting working capital loans. While efforts to create comprehensive credit histories of every woman borrower is underway, technology can be a great enabler in going to scale. The Reserve Bank Innovation Hub and the National Rural Livelihoods Mission are trying to come up with innovations that give confidence to banks to lend on a higher scale. The success of the Start Up Village Enterprise Programme (SVEP) under the NRLM brings out the importance of hand holding, Community Enterprise Fund, and end-to-end solutions for first generation entrepreneurs.

Tenth, start a universal skill accreditation programme for skill providing institutions, and let the state and industry jointly sponsor candidates for courses. Skill providers can be accredited after a rigorous assessment process. Candidates can be co-sponsored by the state and employers.

Eleventh, use 70% funds under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) in 2,500 water-scarce blocks and blocks with high deprivation, with a thrust on the poorest 20 families. Individual beneficiary schemes under MGNREGA allow for livelihood security through income-generating initiatives such as animal sheds, irrigation wells, work sheds, and so on. Focus on skills for higher productivity of MGNREGA wage earners. Better wage rates will facilitate lives of dignity on scale, in very poor regions.

Twelfth, apprenticeships on scale can facilitate the absorption of youth in a workplace. The scale must go up. The focus must be on skill acquisition or else it can get routinised with a stipend being provided, merely as an incentive. The government's condition for employer subsidies in any form must always be for wages of dignity on successful completion of apprenticeship. Let us create a higher order economy, with higher productivity and a higher quality of lives for workmen.

The views expressed are personal

GS Paper 03 : भारतीय अर्थव्यवस्था: रोजगार

(UPSC CSE (M) GS-3 : 2023) भारत में अधिकांश बेरोज़गारी संरचनात्मक प्रकृति की है। देश में बेरोज़गारी की गणना करने के लिए अपनाई गई पद्धति की जाँच करें और सुधार के सुझाव दें। (150 words/10m)

Mains Practice Question : भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर चर्चा करें तथा इस बेरोजगारी की लहर से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। (250 Words)

संदर्भ :

- भारत सरकार ने रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के बड़े पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए अवसर पैदा करना है। यह महत्वाकांक्षी पहल आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। गरिमा के साथ स्थायी रोजगार के बारे में चर्चा कम मजदूरी की चुनौतियों, कौशल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और राज्य के हस्तक्षेप की भूमिका पर प्रकाश डालती है।

वर्तमान चुनौतियाँ और विकेंद्रीकृत कार्रवाई की आवश्यकता

- मजदूरी की चिंताएँ: साक्ष्य बताते हैं कि 25,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला एक वेतनभोगी शीर्ष 10% वेतनभोगियों में से एक है। यह मजदूरी के मामले में सबसे नीचे की ओर दौड़ और सम्मानजनक जीवन के लिए कम वेतन वाली नौकरियों की अपर्याप्तता को उजागर करता है।
- कौशल कार्यक्रम प्रभावशीलता: अल्पकालिक कौशल कार्यक्रम अक्सर अपर्याप्त मजदूरी के कारण दीर्घकालिक रोजगार दरों को कम करते हैं। कई प्रशिक्षित व्यक्ति बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में लौट आते हैं।
- राज्य और स्थानीय भूमिका: गरिमा के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए उत्पादकता बढ़ाने और न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। स्थायी रोजगार को समर्थन देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित नीतिगत पहल

- समुदाय-आधारित कौशल: पहलों को स्थानीय कौशल आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए विकेंद्रीकृत सामुदायिक कार्रवाई से शुरू किया जाना चाहिए। इसमें रोजगार रजिस्टर बनाना और लक्षित योजनाओं को विकसित करने के लिए पेशेवरों के साथ साझेदारी करना शामिल है।
- सेवाओं का एकीकरण: स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार पहलों को एकीकृत करें, जवाबदेही और प्रभावी परिणामों के लिए महिलाओं के सामूहिकों का लाभ उठाएं। यह दृष्टिकोण समुदाय-आधारित निर्णय लेने के माध्यम से मानव विकास संकेतकों को बढ़ाता है।

- व्यावसायिक शिक्षा: कॉलेजों में स्नातक कार्यक्रमों के साथ-साथ आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करें। यह नौकरी बाजार के लिए प्रासंगिक व्यावहारिक कौशल और प्रमाणपत्र प्रदान करके रोजगार क्षमता में सुधार करेगा।

कौशल विकास और समर्थन को बढ़ाना

- मानकीकरण और बुनियादी ढाँचा: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, विशेष रूप से नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य में, को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार मानकीकृत करें। कौशल विकास के लिए केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक को अपग्रेड करने में निवेश करें।
- स्कूलों में उद्यम कौशल: छात्रों को उद्यमशील उपक्रमों और रोजगार के लिए तैयार करने के लिए हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी और उद्यम कौशल को एकीकृत करें। व्यावसायिक दौरे व्यावहारिक समझ और कौशल को बढ़ा सकते हैं।
- प्रशिक्षुता मॉडल: व्यावहारिक अनुभव और साझा लागत सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के साथ प्रशिक्षुता के लिए सह-साझाकरण मॉडल लागू करें। इससे कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और स्थिरता बढ़ेगी।

कम वेतन और अल्पकालिक कौशल कार्यक्रम दीर्घकालिक स्थिरता में बाधा डालते हैं:

- कम वेतन आर्थिक असुरक्षा की ओर ले जाता है: कम वेतन श्रमिकों के लिए आर्थिक असुरक्षा पैदा करता है, जिससे उनके लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, परिधान उद्योग में, प्रमुख परिधान उत्पादक देशों में न्यूनतम वेतन और जीवनयापन वेतन के बीच 48.5% का अंतर है।
- अल्पकालिक कौशल कार्यक्रम रोजगार क्षमता बढ़ाने में विफल होते हैं: कई अल्पकालिक कौशल कार्यक्रम दीर्घकालिक रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की गहराई प्रदान नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में, 75% तकनीकी स्नातक और 90% अन्य स्नातकों को मुख्य रूप से व्यावहारिक कौशल और अनुभव की कमी के कारण बेरोजगार माना जाता है, जिसकी नियोक्ता तलाश करते हैं।
- कार्यबल उत्पादकता में ठहराव: जब श्रमिकों को कम वेतन दिया जाता है, तो उनके लिए अपने कौशल या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन होता है। यह ठहराव व्यक्तिगत करियर विकास और समग्र आर्थिक विकास दोनों के लिए हानिकारक है।
- दीर्घकालिक कौशल विकास में निवेश की कमी: कम वेतन अक्सर कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास में सीमित निवेश से संबंधित होता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षित लोगों में से केवल 15% को ही नौकरी मिली, जो दर्शाता है कि अल्पकालिक प्रशिक्षण पहल प्रभावी रूप से स्थायी रोजगार परिणामों में तब्दील नहीं हो रही है।
- गरीबी और असमानता का स्थायीकरण: कम वेतन और अपर्याप्त कौशल विकास का संयोजन गरीबी और असमानता को बनाए रखने में योगदान देता है। वैश्विक कार्यबल का 42% असुरक्षित रोजगार में है।

स्थायी सामूहिक रोजगार के लिए 12-सूत्रीय नीतिगत पहल:

- कौशल की आवश्यकता की पहचान करें: कौशल आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए विकेंद्रीकृत सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से नीचे से शुरू करें। रोजगार/स्वरोजगार चाहने वालों का एक रजिस्टर बनाएं और क्लस्टर स्तर पर पेशेवरों के साथ साझेदारी में हर युवा के लिए एक योजना बनाएं।
- स्थानीय स्तर पर पहल: सामुदायिक जवाबदेही और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए महिला समूहों के साथ स्थानीय सरकार के स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, पोषण, आजीविका और रोजगार के लिए पहलों को एकीकृत करें।
- व्यावसायिक कार्यक्रम: रोज़गार क्षमता में सुधार के लिए हर कॉलेज में स्नातक कार्यक्रमों के साथ-साथ ज़रूरत-आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम/प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू करें।
- अंतर्राष्ट्रीय मानक पर स्वास्थ्य सेवा: कुशल पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करें।

- महिला सुरक्षा: सार्वभौमिक रूप से क्रेच चलाने के लिए देखभाल करने वालों के सामुदायिक कैडर बनाएँ ताकि महिलाएँ बिना किसी डर के काम कर सकें।
- कौशल विकास में निवेश करें: व्यावसायिक शिक्षा के लिए सबसे कम संस्थागत संरचना वाले राज्यों/जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फीडर स्कूलों के लिए कौशल विकास के केंद्र के रूप में आईटीआई और पॉलिटेक्निक में निवेश करें।
- हाई स्कूल में स्टार्टअप कौशल: छात्रों को फ़िनिशिंग कौशल प्रदान करने के लिए हाई स्कूल में पेशेवरों के माध्यम से उद्यम और स्टार्ट-अप कौशल शुरू करें।
- उद्योग में प्रशिक्षुता कार्यक्रम: उद्योग के साथ प्रशिक्षुता का एक सह-साझाकरण मॉडल (अध्ययन के साथ नौकरी में व्यावहारिक प्रशिक्षण को जोड़ना) रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग की प्रशिक्षुता कार्यक्रम में हिस्सेदारी है।
- कार्यस्थल पर युवाओं का समावेश: बड़े पैमाने पर प्रशिक्षुता कार्यस्थल पर युवाओं के समावेश को सुगम बना सकती है, जिसमें नियोक्ता सब्सिडी के लिए सरकार की शर्त प्रशिक्षुता के सफल समापन पर सम्मानजनक वेतन है।
- महिलाओं के लिए पूंजी ऋण: महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों/पहली पीढ़ी के उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण को सुव्यवस्थित करें ताकि वे बड़े पैमाने पर जा सकें।
- कौशल प्रमाणन कार्यक्रम: कौशल प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए एक सार्वभौमिक कौशल प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करें, जिसमें उम्मीदवार राज्य और नियोक्ताओं द्वारा सह-प्रायोजित हों।
- पानी की कमी वाले ब्लॉक में अधिकांश निधि: 2,500 जल-कमी वाले ब्लॉकों और उच्च वंचितता वाले ब्लॉकों में मनरेगा के तहत 70% निधि का उपयोग करें, जिसमें सबसे गरीब 20 परिवारों पर जोर दिया जाए और उच्च उत्पादकता के लिए कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

GEO IAS
It's about quality

African Union

अफ्रीकी संघ (AU) के बारे में:

- यह एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का निर्माण करते हैं।

- इसे आधिकारिक तौर पर 2002 में लॉन्च किया गया था और इसने अपने पूर्ववर्ती, अफ्रीकी एकता संगठन (OAU) की जगह ली, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी।
- प्राथमिक उद्देश्य: वैश्विक मंच पर महाद्वीप के हितों को आगे बढ़ाते हुए अफ्रीकी देशों के बीच एकता, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना।
- AU अपने "एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका के दृष्टिकोण से निर्देशित है, जो अपने नागरिकों द्वारा संचालित है और वैश्विक क्षेत्र में एक गतिशील शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।"

- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका के पैन अफ्रीकी विज़न की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, एजेंडा 2063 को अफ्रीका के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और एकीकृत परिवर्तन के लिए एक रणनीतिक ढांचे के रूप में विकसित किया गया था।
- एजेंडा 2063 अफ्रीकी लोगों की आकांक्षाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अफ्रीकी नेतृत्व वाली पहलों के लिए अधिक सहयोग और समर्थन का आह्वान करता है।
- मुख्यालय: अदीस अबाबा, इथियोपिया

संरचना:

- सभा: यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं।
- कार्यकारी परिषद: विदेश मामलों के मंत्रियों से बनी, नीतिगत मामलों को संभालती है और विधानसभा को सिफारिशें करती है।
- एयू आयोग: अदीस अबाबा में मुख्यालय, विधानसभा और कार्यकारी परिषद के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक शाखा है।
- शांति और सुरक्षा परिषद: महाद्वीप पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार।
- एयू संरचना पैन-अफ्रीकी संसद और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद (ईसीओएसओसीसी) के माध्यम से अफ्रीकी नागरिकों और नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ावा देती है।

GEO IAS
It's about quality